

<https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/property/-/cstruction/affordable-housing-segment-in-india-to-grow-further-say-real-estate-experts/articleshow/97527783.cms>

Affordable housing segment in India to grow further, say real estate experts

By Faizan Haidar, ET Bureau • Last Updated: Feb 01, 2023, 06:19 PM IST

SHARE FONT SIZE SAVE PRINT COMMENT

Synopsis

Investment in infrastructure has a significant multiplier impact on growth, and the Government has targeted it by increasing the capital investment outlay by 33% to Rs 10 lakh crore, which would be 3.3% of GDP -- three times the outlay made in 2019; the impact would be on increased job potential leading to increased demand for residential real estate.



The increased allocation to housing projects under PM Awas Yojana by 66% to Rs 79,000 crore will help the affordable housing segment, according to real estate experts.

“Rationalization of tax slabs and enhancement of tax rebate is going to benefit the middle class which will

boost domestic consumption and should aid in keeping demand for homes strong,” said Amit Goyal, CEO, [India](#) Sotheby’s International Realty.

The focus on infrastructure and the decision to set up an [Urban Infrastructure Development Fund](#) would also accelerate the housing sector in tier 2 and tier 3 cities.

“The allocation of resources and initiatives aimed at these cities is expected to provide a boost to their economic and social development, making them new hopes for growth and progress in India,” said Vineet Taing, Chief Executive Officer, [Vatika Business Centres](#).

<https://www.financialexpress.com/money/budget-2023-instills-hope-in-real-estate-for-long-term-growth/2969623/>

Budget 2023 instills hope in real estate for long-term growth

Besides the increased fund allocation for PMAY, the measures announced in the budget are expected to have positive implications for the real estate sector in the coming years.

Written by [Sanjeev Sinha](#)

February 2, 2023 17:10 IST



With the increased funding, the government looks to vastly enhance the existing infrastructure and create a conducive environment for investment flow.

India's real estate sector has received a positive push from the Union Budget 2023 presented yesterday. Several measures were announced to encourage investments and stimulate the economy's growth. Besides the increased fund allocation for PMAY, these measures are expected to have positive implications for the real estate sector in the coming years. Realty experts have welcomed these announcements in their response to the Union Budget 2023.

Vineet Taing, Chief Executive Officer, Vatika Business Centres, said, "The Budget for 2023 does indeed place emphasis on the development of tier 2 and tier 3 cities, which are seen as key drivers of growth for the country. The allocation of resources and initiatives aimed at these cities is expected to provide a boost to their economic and social development, making them new hopes for growth and progress in India."

Budget 2023: Many unhappy, but won't say so

Some sops, some missed.



by **Jayashree Mendes** | February 1, 2023

SHARE



What Budget 2021 has for real estate and infrastructure

Nirmala Sitharaman Budget Speech, India Budget 2023: Presenting the Union Budget 2023, Finance Minister Nirmala Sitharaman announces that the capital investment increases for the third year by 33% to 10 lakh crores which come to 3.3% of GDP. The Minister's speech also lays emphasis on infrastructure and jobs ahead of Modi government's last full-fledged Budget before the Lok Sabha elections in 2024.

The finance minister said that the proposal in the budget were around seven priorities: inclusive development, reaching the last mile, infra and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector. The main highlight of the budget was the five major announcements related to personal income tax, including a change in tax slab under the new tax regime.

Vineet Taing, CEO, Vatika Business Centres: The Indian budget for 2023 does indeed place emphasis on the development of tier 2 and tier 3 cities, which are seen as key drivers of growth for the country. The government's focus on these cities is aimed at promoting balanced regional development, creating new job opportunities, and improving the standard of living for citizens in these areas. The allocation of resources and initiatives aimed at these cities is expected to provide a boost to their economic and social development, making them new hopes for growth and progress in India.

लोगों की प्रतिक्रिया



सरकार का ध्यान संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करना और इन क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। - विनीत टैग, सीईओ, चाटिका बिजनेस सेंटर



अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के पुनरुद्धार के मुद्दे को ध्यान में रखा है। पीएम आवास योजना के वरिष्ठ आवंटन में 66% की वृद्धि अच्छी खबर है। - प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर व चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया), लिमिटेड



पीएम आवास योजना फंड में 66 फीसदी की बढ़ोतरी आवास और वाणिज्यिक रियल्टी सेगमेंट के विकास को बढ़ावा देगा। - नवीन एम रहेजा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहेजा डेवलपर्स



सबसे सस्ती क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विशेष रूप से टिपर - 2 और टिपर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति प्रदान करेगी। - मनोज गोड्डा, अध्यक्ष क्रेडिड एनसीआर



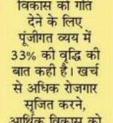
निर्माण गतिविधियों के लिए निवेश में वृद्धि विकास को उत्प्रेरित करके रियल्टी की मांग को बढ़ावा देगी। - अंकित कंसल, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, 360 रीयल्टर्स



पूंजीगत व्यय बढ़ाने से रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आएगी और आवासीय आवास की मांग में वृद्धि होगी। - अश्विनी कुमार, पिरामिड इंप्रोवटेक



विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि की बात कही है। खर्च से अधिक रोजगार सृजित करने, आर्थिक विकास को गति देने और अर्थिक समृद्ध राष्ट्र बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। - कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर अंसल हाउसिंग



विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि की बात कही है। खर्च से अधिक रोजगार सृजित करने, आर्थिक विकास को गति देने और अर्थिक समृद्ध राष्ट्र बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। - कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर अंसल हाउसिंग



पॉलिस्वी कॉर्पस से रियल एस्टेट की मांग और अवसरों में तेजी से वृद्धि होगी। - राजेश के सराफ, एमडी, एक्सओम लैंडबैंक



आयकर छूट, पूंजी निवेश परिलक्ष्य में 33% की वृद्धि से रियल एस्टेट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। - नारायण भड़ाना, एमडी, 4 एस डेवलपर्स



बजट आम जनता को गुमराह करने वाला है। गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम कितने कम होंगे, रेल किराए क्या कम हो जाएंगे। इन बातों का कहीं कोई जवाब नहीं है। - पंकज डाबर, वरिष्ठ कॉर्पोरेट नेता



वित्त मंत्री ने अमृत काल का लोक कल्याणकारी बजट पेश कर देश के साथ वैश्विक आकांक्षाओं पर खरा उतरने की प्रतिबद्धता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। - जीएल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा

पंजाब केसरी

BUDGET 2023

भारत सरकार के बजट पर गुलुग्राम के उद्योग जगत के लोगों की प्रतिक्रियाएं

बैलेंस बजट, उद्यमी-कारोबारी खुश

गुडगांव, 1 फरवरी (संजय): बुधवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट देश के सामने रखा। बुधवार पूरे दिन बजट परिचर्चा पर उद्यमियों व कारोबारियों की नजर रही। पेश है शहर के दिग्गज कारोबारी व उद्यमियों की राय। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में घोषणाएँ, जैसे कि कर राहत, शिक्षा में सुधार और अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना, उत्साहजनक हैं।

आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पेटर्न पवन यादव ने कहा केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बेहद सकारात्मक है। कोरोना काल की चुनौतियां झेल चुके लोगों के लिए ये बजट लोगों के संभालने की एक बेहतरीन कोशिश है। 2023-24 के बजट में 10.5 लाख करोड़ दिया गया। साल 2019 में यह पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ रुपये था। जबकि 2021 में यह 7.5 लाख करोड़ था। न्यू टैक्स रिजिम (नई टैक्स व्यवस्था) में 7 लाख करने का प्रस्ताव है।



एमएफ फाउंडेशन की ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया ने कहा समावेशी विकास, हरित विकास व युवा शक्ति पर फोकस के साथ इस साल का बजट बहुत उत्साहजनक है। विभिन्न क्षेत्रों में घोषणाएँ, जैसे कि कर राहत, शिक्षा में सुधार, और अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना, उत्साहजनक हैं। स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन 2022-23 में 63,449 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) से बढ़ाकर 2023-24 में 68,804 करोड़ रुपये करना शिक्षा क्षेत्र के लिए एक स्वगत योग्य कदम है।



अल्फा कॉर्प के एजीक्यूटिव डायरेक्टर संतोष अग्रवाल ने कहा अफोर्डेबल हाउजिंग सेक्टर में दूरदर्शी विकास के साथ, एफएम ने पीएमएवाई के तहत 79,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इससे अफोर्डेबल सेगमेंट में हाउसिंग डिमांड को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी ओर, इन्फ्रास्ट्रक्चर-कैपेक्स पर दिया गया जोर संभावित टियर क्षेत्रों को रोजगार, विकास व सरटेनेबल लिविंग में मदद करेगा।



'कोरोना काल की चुनौतियां झेल चुके लोगों के लिए ये बजट उन्हें संभालने की एक बेहतरीन कोशिश'



सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्वर्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक अरविंद कुमार ने इसे अमृतकाल का बजट बताया। देश में समावेशी विकास व रोजगार के मार्ग प्रशस्त करने वाला है। बजट उभरती प्रौद्योगिकियों व बेहतर व्यावसायिक नीतियों, केंद्रित पहल, व डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सशक्त बनाएगा।



त्रेहान आइरिस के कार्यकारी के निदेशक अमन त्रेहान ने केन्द्रीय बजट 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 है। इस बड़ी हुई फंडिंग के साथ, सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से बढ़ाने व निवेश प्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर विचार कर रही है। आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।



प्रवीण जैन नारडको के चेयरमैन ने कहा बजट-2023 में ग्रीन ग्रोथ यानि हरित विकास पर अधिक ध्यान देते हुए जीरो कार्बन उत्सर्जन, अधिक ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन एनर्जी का उत्पादन, कम कार्बन उत्सर्जन, फॉसिल फ्यूल पर कम निर्भरता, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रिड इंटीग्रेशन, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, के नए लक्ष्य तय किए गए हैं। इस के साथ ही पीएम-प्रणाम योजना, गो-वर्धन योजना, ग्रीन एपी-ड्राइव, अमृत-धरोहर जैसी गो ग्रीन योजनाएं, बायोमास, जैव विविधता के लिए जैव-पौधों पर जोर दिया गया है।



वाटिका बिजनेस सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत टैग ने कहा 2023 के लिए भारतीय बजट वास्तव में टीयर-2 व टीयर-3 शहरों के विकास पर जोर देता है। जिन्हें देश के लिए विकास के प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है। इन शहरों पर सरकार का ध्यान संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करना और इन क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इन शहरों के लिए लक्षित संसाधनों और पहलों के आवंटन से उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।



वीहांट टेक्नोलॉजीज के सीईओ व को फाउंडर कपिल बरदेजा ने कहा भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, उद्योग व शिक्षा जगत के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। एक उद्योग भागीदार के रूप में, हमारा मानना है कि इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

